परिणामी बजट वर्ष 2020-21

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	भिलाई में साफ्टवेयर पार्क की स्थापना	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गतिविधियों के विस्तार एवं विकास हेतु भिलाई में स्थापित किया गया है।	651	भिलाई नगर निगम को मंगल भवन, के मासिक किराये का भुगतान किया जाता है।	
2	स्वान परियोजना	छत्तीसगढ़ के समस्त कार्यालयों को जोड़ने हेतु सूचना तंत्र का निर्माण	230000	राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर सभी कार्यालयों को सूचना आदान प्रदान हेतु कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना	
3	डिजिटल शासन की स्थापना	शासन के कार्यो में ऑनलाइन कार्यप्रणाली को बढ़ावा देना	15300	1. कोर्ट केस प्रबंधन का डिजिटल सचिवालय एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन 2. मैन्युअल फाईल ट्रेकिंग सिस्टम (क्यू.आर. कोड़ के साथ) का विकास एवं क्रियान्वयन 3. नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम (के.एम.एस.) का क्रियान्वयन 4. नए सिस्टम इंटीग्रेशन का निविदा के द्वारा चयन 5. परियोजना के वर्तमान सिस्टम इंटीग्रेशन के साथ निकास प्रबंधन (एक्जीट मैनेजमेंट) का कार्य	
4	सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना	ग्रामों में नागरिकों को ई-गवर्नेस एवं ई-भुगतान की सेवाएँ प्रदान करना	1	सामान्य सेवा केन्द्रों का संचालन करना	
5	ई-जिला परियोजना	शासन की प्रमुख जी.2सी. सेवाएँ, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु सॉफ्टवेयर एवं अधोसंरचना का विकास	65000	प्रचालन एवं रखरखाव, लाइसेंस का ए.एम.सी., एस.एम.एस. सेवा, मानव संसाधन, नई सेवओं और अन्य विविध आवश्यकताओं के लिए	
6	कोर इनक्यूबेटर-सह-एक्सेलरेटर संस्थान	राज्य में स्टार्टअप तथा इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिजनेस इनक्यूबेटर की स्थापना तथा प्रचालन किया जा रहा है।	22470	1. 100 से अधिक स्टार्टअपस को इन्क्युबेट किया गया है। 2. स्टार्टअप द्वारा 700 से अधिक रोजगार प्रदान किया जाना 3. राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स में 36 आई.एन.सी. के साथ 2 अन्य स्टार्टअप प्रकाशित हुए।	

परिणामी बजट वर्ष 2020-21

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
				4. कई स्टार्टअपस ने अंतराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पुरस्कार जीत है। 5. टेक्मेंट नामक स्टार्टअप के प्रोडक्ट को अमेरिका स्थित एक कंपनी ने एक्वायर किया है। 6. 36 आई.एन.सी. में स्थित स्टार्टअप फिनोलोजी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथम फाइनेंशियल सलाहकार संस्था है।	
7	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस प्रशिक्षण संस्थान	नेशनल ई-गवर्नेंस आशिक्षण - शासकीय सेवकों को आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस में संबंधित आशिक्षण देना	5000	राज्य लोक सेवा आयोग में चयनित नवनियुक्ति डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, लेखाधिकारी आदि को आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस में संबंधित प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी में प्रदान करना।	
8	सेन्ट्रल मॉनिटरिंग यूनिट फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर	राज्य के प्रमुख अधोसंरचना निर्माण की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी एवं समीक्षा	7500	लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण एवं मॉनिटरिंग टीम की स्थापना	
8	एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना	ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभागों की निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं कुशल बनाना	15000	विभिन्न विभागों तथा उनकी एजेंसियों को निविदा कार्य हेतु ऑनलाईन सुविधा	
9	नागरिक संबंध केन्द्र योजना	शासन की जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन की हितग्राहियों की प्रतिक्रिया के आधार पर समीक्षा	10000	एक कॉल सेंटर की स्थापना एवं समस्त हितग्राहियों के समेकित डेटाबेस का विकास कर शासन की महत्वपूर्ण हितग्राही मूलक योजनाओं का 'फीडबैक' लेना	

परिणामी बजट वर्ष 2020-21

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
10	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की योजना	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु निवेशकों को आकर्षित करना एवं नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट प्रदान करना	110000	सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना एवं रोजगार करने हेतु निवेशकों को आकर्षित करना एवं नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट प्रदान करना	
11	जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी का संचालन	ई-गवर्नेंस कार्यो के लिए जिला स्तर पर संचालन हेतु अमला उपलब्ध कराना	17422	27 जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी का संचालन करना	
12	वाई-फाई सिटी की योजना	नागरिकों को सर्वाजनिक स्थलों पर नि:शुल्क इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना	5200	राज्य के प्रमुख क्षेत्रों/शहरों में वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाना	
13	विशिष्ट पहचान (आधार) परियोजना	राज्य में आधार योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन करना	7000	राज्य के आधार इनरोलमेंट एजेंसी के रूप में चिप्स को तथा पंजीयक के रूप में इ.सू.प्रौ. विभाग को कार्य करने हेतु सक्षम करना	
14	भारत नेट परियोजना	राज्य में ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क का विस्तार करना	150010	ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाना	
15	छत्तीसगढ़ स्टेट स्पासियल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर	राज्य में भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित सूचनाओं को सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय विभागों हेतु केन्द्रीकृत करना।	26394	विभागों को जीआईएस प्लेटफार्म पर ऑनलाईन प्रदान करना	
16	स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	छत्तीसगढ़ स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	313800	विभागों की प्रमुख सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स एवं डेटा को होस्ट करने हुत स्टेट डाटा सेंटर एवं क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना	
17	संचार क्रांति योजना	राज्य में मोबाइल नेटवर्क का विस्तार एवं मोबाईल के उपयोग को बढ़ावा देना	1000000	मोबाइल वितरण और सेवाओं के लिए कॉन्ट्रेक्टर का लंबित भुगतान	
18	छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन योजना अंतर्गत एकीकृत सक्रिय ई-शासन प्रणाली परियोजना	200000		

परिणामी बजट वर्ष 2020-21

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
		(आई.पी.ई.जी.-7919) की विविध आवश्यकताओं के लिए		1. नीति नियोजन उपकरण का डिप्लॉइमेन्ट 2. डाटा शेयरिंग एवं सहमति फ्रेमवर्क नीति और दिशानिर्देशों की अधिसूचना हेतु 3. डायनेमिक लाभार्थी रजिस्ट्री एवं डेटा एक्सचेंज प्लेटफार्म के रोलआउट हेतु 4. ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का आई.पेग में माइग्रेशन हेतु	
19	स्टेट पोर्टल परियोजना	परियोजनांतर्गत विकसित नवीन स्टेट पोर्टल हेतु मानव संसाधन की आवश्यकता होगी जिस हेतु हार्डवेयर आईटम एवं सॉफ्टवेयर लाईसेंस स्टेट डाटा सेन्टर द्वारा प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है।	2848	परियोजना का प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है:- राज्य के नवीन पोर्टल एवं पोर्टल की थीम पर विकसित वेबसाईट का रखरखाव सुनिश्चित करना। पोर्टल एवं अन्य वेबसाईट पर नियमित रूप से जानकारी अद्यतन किया जाना एवं अपलोड करना। पोर्टल एवं अन्य वेबसाईट के सर्वर का वार्षिक रखरखाव करना। विभिन्न विभागों शासकीय सेवकों एवं नागरिकों को वेबसाईट के माध्यम से उपयोगी जानकारी, टेण्डर, अधिसूचना आदि के संबंध में जानकारी प्रदान करना।	
20	छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी की स्थापना	स्थापना मद अंतर्गत कार्यालयीन व्यय आदि का रखरखाव एवं संधारण	115000	चिप्स हेतु स्थायी कार्यालय की स्थापना, जो स्मार्ट सिटी के आई.टी की आवश्यकता में महत्वपूर्ण है।	
21	मुख्यमंत्री ई-समीक्षा	शासन के विभागों के प्रदर्शन की समेकित समीक्षा	40000	डैशबोर्ड का निर्माण, जिसमें शासकीय विभागों के मुख्य निष्पादन संकेतक के आधार पर योजनाओं के प्राथमिकता एवं प्रगति के निगरानी	
22	सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना	एस.टी.पी.आई. के साथ एन.आई.टी रायपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना	20000	अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप एवं स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम में योगदान	

परिणामी बजट वर्ष 2020-21

विभाग- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

विभागाध्यक्ष- सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2020-21	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
23	बिल्डनेक्स्ट परियोजना	शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों का वेबसाईट का डिजाईन, संचालन एवं एप्लीकेशन निर्माण करना तथा इसके लिये इन-हाऊस मैनपावर की भर्ती किया जाना	30000	छत्तीसगढ़ शासन के सभी शासकीय विभागों के वेबसाईटों एवं मोबाईल एप्लीकेशन की लागत को 30-40 प्रतिशत कम कर एवं कार्य के गुणवत्ता को बढ़ा देना	